बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 5

04 चैत, 1939 (श.)

शनिवार, तिथि ----------

25 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 24

1.	शिक्षा विभाग	....	....	22
2.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	....	....	01
3.	खान एवं भूतत्व विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**24**

निगम में हेराफेरी

***** 377. **श्री मंगल पांडेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक निगम के अधिकारियों व प्रिंटिंग प्रेस की मिलीभगत से पाठ्यपुस्तक छपाई, सेटमेकिंग, ट्रांसपोर्टिंग का सभी कार्य करने का टेंडर एक ही कंपनी को विगत वर्ष 2011 से लगातार दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक निगम प्रिंटिंग प्रेस की पुस्तक छपाई के लिए कागज मुहैय्या कराता है, लेकिन जितना कागज प्रेस को दिया जाता था, उस अनुपात में पुस्तक की छपाई नहीं की जाती थी, परिणामस्वरूप विद्यार्थी को समय पर कभी भी पुस्तक नहीं मिल पाती। आधी छपाई होती थी, आधे कागज को बाजार में पदाधिकारी/ठेकेदारों के द्वारा बेच दिया जाता था जिससे पाठ्यपुस्तक निगम में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिस पदाधिकारी की मिली-भगत से पाठयपुस्तक छपाई टेंडर में भारी हेराफरी की गयी है, उसकी उच्चस्तरीय जांच कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

भवन निर्माण कबतक

***** 378. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलांतर्गत लखनौर प्रखंड के गंगापुर पंचायत में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, गुनाकरपुर के लिए जमीन दाता रामेश्वर साहू द्वारा 4 कट्ठा, 10 धुर जमीन दिनांक 21.10.2006 में ही महामहिम राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री के बावजूद अभी तक भवन निर्माण नहीं हो सका है, जबकि उस समय पैसा भी उपलब्ध था;

(ख) क्या यह सही है कि अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के पत्रांक-170/रा.गो., दिनांक 3.9.2009 एवं समाहर्त्ता, मधुबनी, अपर समाहर्त्ता, मधुबनी एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मधुबनी का संयुक्त पत्र पत्रांक-267/जी.रा., दिनांक 18.01.2010 द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, मधुबनी को शीघ्र विद्यालय भवन निर्माण का आदेश दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय, गुनाकरपुर का भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

मैथिली शिक्षकों की बहाली

* 379. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा मैथिली है;

(ख) क्या यह सही है कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में मैथिली भाषा की पढ़ाई हेतु शिक्षकों का अभाव है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में मैथिली शिक्षकों की बहाली करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

समान वेतन

* 380. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सरकार राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम का नियमित शिक्षकों की तुलना में समान वेतन नहीं दे रही है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में सूबे के अंदर विभाग, नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभाव की नीति अपना रहा है, जिससे उन शिक्षकों में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है और वे समान वेतन की खातिर हड़ताल करने के लिए विवश रहते हैं और विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्कूलों की पढ़ाई सुदृढ़ करने के लिए नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का विचार रखती है, ताकि नियोजित शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों के बीच भेदभाव समाप्त हो सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

परीक्षाफल का प्रकाशन

* 381. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सबसे अधिक छात्र मगध विश्वविद्यालय के हैं, लेकिन सबसे अधिक परेशानी इसी विश्वविद्यालय के छात्रों को होती है;

(ख) क्या यह सही है कि एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा, एग्जाम, रिजल्ट और एकेडमिक के अलावा अन्य ऐक्टिविटी कराकर छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने में यह पूरी तरह से असफल रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाफल परीक्षा के 7 से 8 महीने बाद प्रकाशित होता है;

(घ) क्या यह सही है कि सालों-साल लेट-लतीफी के कारण यहां छात्रों का कैरियर बर्बाद हो रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मगध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की परीक्षा एवं परीक्षाफल का प्रकाशन सही समय पर करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नियोजन नियमावली

***** 382. **श्री केदारनाथ पांडेय**: क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजकीय/राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में +2 स्तर तक सभी विषयों की पढ़ाई शुरू की जा चुकी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कोटि के विद्यालयों में +2 स्तर तक के विषय के शिक्षकों की भारी कमी है जिसके कारण विद्यालयों का पठन-पाठन सुचारु रूप से संभव नहीं हो पा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जटिल होने के कारण शिक्षकों की नियुक्तियां समयानुसार नहीं हो पाती हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजन नियमावली की जटिल प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए उक्त कोटि के विद्यालयों में शीघ्र शिक्षकों की नियुक्तियां करना चाहती है?

कोचिंग नियमावली

* 383. **श्री रजनीश कुमार**: क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 2010 में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम बनाया था जिसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों का निबंधन अनिवार्य किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में सिर्फ पटना में चार हजार से अधिक एवं अन्य जिलों में हजारों कोचिंग संस्थान बगैर निबंधन के चल रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि अबतक पूरे राज्य में सिर्फ 500 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार कोचिंग नियमावली, 2010 के तहत कोचिंग संस्थानों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कठोर कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वेतनादि का भुगतान

* 384. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए विधान मंडल द्वारा स्वीकृत बजट की राशि के बावजूद 6-6 महीने तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है;

(ख) क्या यह सही है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की जवाबदेही शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की होती है, लेकिन बेगुनाह शिक्षकों के वेतन बंद कर दिये जाते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शिक्षकों के खाते में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतनादि के भुगतान की व्यवस्था कबतक सुनिश्चित करना चाहती है ?

आधारभूत सुविधाएं कबतक

* 385. **श्रीमती नूतन सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के चैनपुर ग्राम में अवस्थित उच्च विद्यालय चैनपुर-पड़री में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय का अहाता समतल नहीं है और विद्यालय में चहारदीवारी भी क्षतिग्रस्त है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में गणित एवं विज्ञान संकाय के शिक्षक नहीं हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं की परेशानी को देखते हुए पेयजल, चहारदीवारी, अहाते का समतलीकरण, गणित एवं विज्ञान संकाय के शिक्षकों की व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

छात्र संघ कोष का गठन

***** 386. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विगत 32 वर्षों में छात्र संघ के नाम पर पटना विश्वविद्यालय में छात्रों से लाखों रुपये वसूले गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि पटना विश्वविद्यालय में अभी तक कोई छात्र संघ कोष का गठन नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करने पर भी उन राशियों का हिसाब देने में असमर्थ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से वसूली गई राशि का उपयोग छात्रों के किस हित में हुआ, यह बताने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

10+2 की पढ़ाई

***** 387. **श्रीराधाचरण साह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला में अगिआंव प्रखंड के सर्वोदय उच्च विद्यालय में 10+2 विद्यालय का भवन बना हुआ है;

(ख) उक्त विद्यालय को 10+2 की पढ़ाई के लिए कब मान्यता दी गई और इसका भवन कब बनकर तैयार हुआ;

(ग) क्या यह सही है कि अगिआंव प्रखंड एक पिछड़ा क्षेत्र है इसके बावजूद भी अभी तक इस विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित नहीं की जिसके कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इस विद्यालय में 10+2 की पढ़ाई शुरू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आश्रितों को अनुदान

***** 388. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1062, दिनांक 08.09.2015 एवं ज्ञापांक-1063, दिनांक 08.09.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं के द्वारा नियोजित प्राथमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को एकमुश्त राशि 4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रखंड एवं विद्यालयों के पांच शिक्षकों की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो गई;

(ग) क्या यह सही है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा विभाग, खगड़िया ने अपने ज्ञापांक-2650, दिनांक 20.10.16 द्वारा निदेशक (प्रा. शि.), बिहार, पटना से अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु मांग की है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक शिक्षकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

कमरे का निर्माण

* 389. **श्री सच्चिदानंद राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत श्री ढ़ोढ़नाथ उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज, लहलादपुर में ग्यारहवीं एवं बारहवीं में 480 बच्चे एवं कक्षा 9वीं एवं 10वीं में 2700 बच्चे नामांकित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में मात्र तीन कमरे हैं जिसके एक कमरे में कार्यालय तथा दो कमरे में लगभग तीन हजार बच्चों की पढ़ाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुपात में कक्ष हेतु कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सेवा नियमित कबतक

* 390. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की विभिन्न खंडपीठों द्वारा पारित न्यायादेशों में स्पष्ट है कि अगर दस वर्षों तक विभागान्तर्गत सृजित एवं स्थायी तौर पर रिक्त व्याख्याता पदों के विरुद्ध अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (A.I.C.T.E) द्वारा लागू निर्धारित अर्हता एवं मापदंडों के अनुरूप आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए हो, तो 6 माह के अंदर ONE TIME REGULARISATION प्रक्रिया अपनाते हुए नियमितीकरण किया जाए;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य की सभी राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों में विगत दस वर्षों से कार्यरत संविदा व्याख्याताओं की सेवा नियमित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

दोषी पर कार्रवाई

* 391. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंडान्तर्गत वायसी एवं करआईन ग्राम पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं वी.आर.पी. द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में सरकार की ओर से मिड-डे मील, पोशाक योजना एवं छात्रवृत्ति योजना भी चल रही है;

(ग) क्या यह सही है कि औचक निरीक्षण के बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को आवास पर बुलाकर खंड 'क' में वर्णित पदाधिकारीगण द्वारा स्थानीय मुखिया एवं सरपंच की मदद से धमकी देकर मोटी रकम की उगाही की जाती है, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश व्याप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है ?

नवसृजित विद्यालय की स्थापना

***** 392. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों को जमीन नहीं मिलने के कारण उक्त विद्यालय को बगल के स्कूल में समायोजित किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि भवनविहीन नवसृजित विद्यालयों को जहां अभी पठन-पाठन हो रहा है, उसे तीन किलोमीटर दूरी तक दूसरे विद्यालयों में समायोजन किया गया है जिससे बच्चों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने उस बस्ती में नवसृजित विद्यालयों की स्थापना क्यों की ?

अवैध खनन पर रोक

***** 393. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बांका जिलान्तर्गत चान्दन नदी से बालू खनन का उठाव (बन्दोबस्त) संवेदक, महादेव इन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित कंपनी द्वारा जिस घाट की नीलामी नहीं हुई है उस घाट से भी संवेदक तथा असामाजिक प्रवृत्ति के दबंगों द्वारा बालू के अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बांका जिले के चान्दन नदी से अवैध बालू खनन का उठाव करने वाले संवेदक को दी गई बन्दोबस्ती को रद्द करने एवं असामाजिक प्रवृत्ति के दबंगों के द्वारा अवैध बालू के खनन कार्य को रोकना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कानून लागू कबतक

***** 394. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार शिक्षा का अधिकार कानून को पूर्णरूपेण लागू करने में असमर्थ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना के 1190 निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में 25 फीसदी गरीब एवं अभावग्रस्त बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में भी करने का प्रावधान है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शिक्षा का अधिकार कानून सख्ती से लागू हो, इसके लिए किन-किन स्कूलों पर कार्रवाई की है, नहीं तो क्यों ?

किताबों का वितरण

***** 395. **मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सरकार की यह नीति है कि विद्यालयों में उर्दूभाषी छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए प्रत्येक विषय की किताबों को उर्दू भाषा में उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो अबतक कितनी किताबें उर्दू में छापी गईं एवं कितनी किताबों का वितरण उर्दूभाषी छात्रों को किया गया ?

विशेष अवकाश की मांग

***** 396**. श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिन विशेष अवकाश लेने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि 50 वर्ष उम्र के ऊपर की महिला कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू है;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है, उन्हें विशेष अवकाश देने से वंचित रखा जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अन्य विभागों की तरह 50 वर्ष से ऊपर की महिला शिक्षिकाओं को भी दो दिन का विशेष अवकाश देने का सरकार विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

आपूर्ति कबतक

***** 397. **श्री अर्जुन सहनी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंडान्तर्गत उच्च विद्यालय, नदियामी एवं उच्च विद्यालय, मछैता में भवन, चहारदीवारी एवं डेस्क-बेंच के अभाव के कारण छात्रों को पठन-पाठन में काफी असुविधा हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, दरभंगा की दिनांक 02.08.2016 की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त विद्यालय में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सरकार भवन, चहारदीवारी का निर्माण एवं डेस्क-बेंच की आपूर्ति शीघ्र कराये;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दोनों उच्च विद्यालयों में भवन, चहारदीवारी का निर्माण एवं डेस्क-बेंच की आपूर्ति शीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नामांकन में राशि की मांग

***** 398. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पटना वीमेंस कॉलेज, पटना भी आता है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा घोषित उच्च शिक्षा में छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन घोषित होने के बाद भी पटना वीमेंस कॉलेज में छात्राओं से नामांकन में 60 (साठ) हजार मोटी रकम लेकर नामांकन किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पटना वीमेंस कॉलेज में छात्राओं के नामांकन के लिए राशि की जांच कराकर रोक लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वेतन का निर्धारण

***** 399. **श्री देवेश चंद्र ठाकुर** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 429 कोटि के संस्कृत विद्यालयों में से 86 विभिन्न कोटि के संस्कृत विद्यालय में से 40 संस्कृत विद्यालय का 1 फरवरी, 2015 से अद्यतन वेतन भुगतान लंबित है, जबकि संबंधित जिला से सितंबर, 2015 में ही व्यय मांग पत्र प्राप्त हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के 531 संस्कृत विद्यालयों का वेतन निर्धारण 01.04.2013 से कर दिया गया है, परन्तु 86 कोटि के संस्कृत विद्यालयों में से 40 विद्यालयों का वेतन पुनरीक्षण आज तक नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उन गरीब संस्कृत शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर वेतन भुगतान शीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आवासीय सुविधा

***** 400. **श्री हीरा प्रसाद बिन्द** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अवस्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आवासीय सुविधा के साथ छात्राओं को वर्ग आठ तक की शिक्षा प्रदान की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि इस विद्यालय से वर्ग आठ की शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त निर्धन एवं गरीब छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा के साथ आगे की पढ़ाई जारी रखने की कोई व्यवस्था राज्य में नहीं है जिससे वे आगे की शिक्षा जारी नहीं रख पाती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं हेतु आवासीय सुविधा के साथ इन्टर स्तर तक की पढ़ाई प्रारम्भ करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 25 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्